+

प्रेषक,

सुबर्द्धन, सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में.

आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड देहरादुन।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक र् मार्च, 2013 विषय:— जनपद नैनीताल के स्थान कालाढूँगी में प्रस्तावित कुकिंग गैस एजेन्सी के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कुमायूँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड के पत्र संख्या 1532/11—गैस दिनांक 05.07.2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें प्रबन्ध निदेशक, कुमायूँ मण्डल विकास निगम ने जनपद नैनीताल के स्थान कालाढूँगी में प्रस्तावित गैस एजेन्सी के निर्माण हेतु ₹ 72.30 लाख (रूपये बहत्तर लाख तीस हजार मात्र) का आगणन गठित कर वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रेषित किया है। प्रबन्ध निदेशक, कुमायूँ मण्डल विकास निगम द्वारा तैयार आगणन ₹ 72.30 लाख को टी०ए०सी० द्वारा परीक्षणोपरान्त आगणन की आंकलित धनराशि ₹ 65.57 लाख (रूपये पैंसठ लाख सतावन हजार मात्र) को औचित्यपूर्ण माना है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012—13 में कुकिंग गैस एजेन्सी के गैस गोदाम आदि के निर्माण हेतु प्रथम किस्त के रूप में ₹ 20.00 लाख (रूपये बीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

- 1— कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- 2— कार्य स्थल पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व तकनीकी दृष्टि से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर ली जाय एवं अनुमन्य व प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।
- 3— निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री प्रयोग में लायी जाय।
- 4— अगगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 5— निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि वर्णित स्थल पर गैस एजेन्सी खोलने व गैस गोदाम निर्माण हेतु समस्त अनुमतियां प्राप्त हो गयी हैं।
- 6— निर्माण कार्य प्रारम्भ करने एवं इस हेतु निर्माण सामग्री आदि क्रय करने से पूर्व Uttarakhand Procurement Rules 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका व बजट मैनुअल के सुसंगत प्राविधानों तथा मितव्ययता का पालन कडाई से किया जायेगा।

PS- Letter- 2011-12 new

7— यह सुनिश्चित किया जाय कि भूमि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के स्वामित्व में रहेगी और तद्नुसार तत्काल भूमि विभाग के नाम हस्तान्तरित की जायेगी।

8— यह भी सुनिश्चित किया जाय कि वर्णित भूमि में निर्मित होने वाले भवनों पर भी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का स्वामित्व रहेगा और नियमानुसार निर्धारित किये गये दर पर मासिक किराया कु0म0 विकास निगम से सरकार के पक्ष में नियमित आधार पर जमा किया जाय एवं देरी से किराया जमा होने की दशा में लम्बित किराया राशि पर दस प्रतिशत की दर से व्याज देय होगा।

9— पूर्व वर्षो में गैस एजेन्सी एजेन्सी/गैस गोदाम हेतु कु0म0 विकास निगम अथवा गढवाल मण्डल विकास निगम को अवमुक्त की गयी धनराशियों के सम्बन्ध में भी उपरोक्तानुसार भवन व भूमि का स्वामित्व खाद्य विभाग के नाम कराते हुए देय किराया व जारी किराया पर व्याज की वसूली सुनिश्चित की जाय।

10— उक्त धनराशि का आहरित कर कार्यदायी संस्था कुमायूँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड नैनीताल को उपलब्ध करायी जायेगी।

11— उक्त धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिस हेतु स्वीकृत की जा रही है।

12— चालू वित्तीय वर्ष 2012—13 में इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान सं० 25 के लेखाशीर्षक 4408—खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण पर पूंजीगत परिव्यय—02—भण्डारण तथा भण्डागारण—आयोजनागत—800—अन्य व्यय—00—07 गैस गोदामों का निर्माण—24—वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

13— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं0 125 P/XXVII(5)2012-13 दिनॉक 22.03.2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय (सुबर्द्धन) सचिव।

संख्या | ५५(i)/13-XIX-2/12 खाद्य/2005 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।

2— आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।

3- प्रबन्धक निदेशक, कुमायूँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड़ नैनीताल।

4- वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

5- जिलाधिकारी/जिलापूर्ति अधिकारी, नैनीताल

6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।

7- वित्त अनुभाग-5/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।

8— समन्वयक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।

9- गार्ड फाईल।

